RAJYA SABHA

Friday, the 7th March, 2003/16 *Phalguna,* 1924 (*Saka*)

The House met at Eleven of the Clock,

MR. CHAIRMAN in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*241. [*The questioner (Shri N.K. Premachandran) was absent. For answer* vide *page* 40-41 *infra.*]

शिक्षा की सुविधाओं से वंचित जिले

*242. **श्रीमती प्रेमा करियप्पा:** ††
श्री मोती लाल वोरा:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख तक देश में ऐसे कुल कितने जिले हैं; जहां बच्चों को प्राथमिक शिक्षा हेतु विद्यालय भेजने का प्रबंध नहीं किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने गरीबी और भुखमरी से त्रस्त बच्चों को विद्यालय भेजने हेतु कोई विशेष योजना बनाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

सभा में यह प्रश्न श्रीमती प्रेमा करियप्पा द्वारा पूछा गया।

विवरण

(क) प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था-विहीन कोई जिला नहीं है।

---

††सभा में यह प्रश्न श्रीमती प्रेमा करियप्पा द्वारा पूछा गया।

(ख) से (घ) प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान नामक एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया है जिसके अन्तर्गत अनुमानित आवश्यकताओं के आधार पर जिलों द्वारा जिला प्रारंभिक शिक्षा योजनाएं तैयार की जाती हैं।

सरकार लक्षद्वीप को छोड़कर (जिसकी अपनी योजना है) सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में मध्याह्न भोजन योजना भी कार्यान्वित कर रही है जिसके अन्तर्गत सरकारी, सरकारी सहायता-प्राप्त तथा स्थानीय निकाय प्राथमिक स्कूलों के साथ-साथ शिक्षा गारंटी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा के अन्तर्गत स्थापित किए गए अध्ययन केन्द्रों में पढ़ रहे बच्चों को भोजन देने के लिए राज्यों को 100 ग्राम प्रति बच्चा प्रतिदिन की दर से खाद्यान्न दिया जाता है।

हाल ही में संविधान (86वां संशोधन) अधिनियम, 2002 लागू किया गया है जिसमें 6-14 आयु-वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है।

Districts without education facilities

†*242. SHRIMATI PREMA CARIAPPA:††
SHRI MOTILAL VORA:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) number of districts in the country as on date where arrangements have not been made to send the children for primary education;

(b) whether Government have formulated any special scheme to send the poor children and those suffering from poverty and starvation to school;

(c) if so, the details thereof; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DR. MURLI MANOHAR JOSHI): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

†Original notice of the question was received in Hindi.

††The question was actually asked on the floor of the House by Shrimati Prema Cariappa.

Statement

(a) There is no district in the country which does not have facilities for primary education.

(b) to (d) To ensure universalisation fo elementary education, the Government has launched the National Programme of Sarva Shiksha Abhiyan under which District Elernentary Education Plans are prepared by the districts based on the requirements projected.

Government is also implementing the Mid-day Meal Scheme in all States and U.Ts. except Lakshadweep (which has its own scheme) under which foodgrain at the rate of 100 grams per child per day is supplied to States for provision of a meal to the children in Government, Government-aided and local body primary schools as well as, learning centres established under EGS&AIE.

Recently the Constitution (86th Amendment) Act, 2002 has been enacted to make Education for Children in the age group 6-14 years a Fundamental Right.

SHRIMATI PREMA CARIAPPA: Sir, there are many Government primary schools without proper infrastrucure. Many times, students are forced to sit outside, because school buildings are either dilapidated or very old. I would like to know from the hon. Minister whether the Government has made any assessment of the financial assistance needed for providing the minimum infrastructure to a primary school. If so, the details thereof?

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: श्रीमन्, इसके लिए प्रत्येक राज्य से हम जानकारी लेते हैं और उसके अनुसार हम वहां व्यबस्थाएं भी करते रहते हैं। मैं आपको इसके बारे में बता सकता हूं कि कितने विद्यालयों में, कितने स्थानों पर अभी तक हमने व्यवस्था की है और आगे हम बराबर उसका इंतजाम करते रहते हैं। अनेक स्थानों पर हमने नए भवन बनाए हैं, अनेक स्थानों पर भवनों में नए कक्ष जोड़े हैं, बच्चों के लिए शौचालय बनाए हैं और पेयजल की व्यवस्था की है। जैसे जानकारी आती है, वैसे हम उस प्लान को एप्रूव करते हैं, उसका एप्रेजल करते हैं और सरकारों की मदद करते रहते हैं। इसकी जो जानकारी है वह इस प्रकार से है कि हमने सर्व शिक्षा अभियान में पिछले तीन सालों में और डीपीईपी में 89,675 स्कूल बनाए हैं, 1,31,813 टीचर्स दिए हैं, 55,510 स्कूल बिल्डिंग्ज बनाई हैं। इसी तरह से 85,798 एडीशनल क्लास रूम्ज बनाए हैं, 1,13,512 टॉयलेट्स बनाए हैं और ड्रिंकिंग वॉटर 65,180 हैं This is the progress of the scheme, and if

other things come]अगर हमारे पास और जानकारियां आती हैं तो उसके हिसाब से हम प्लान एप्रूव करते हैं। फिर फाइनांस मिनिस्ट्री पैसा देती है तो हम कर देते हैं।

SHRIMATI PREMA CARIAPPA: Sir, it is known to everybody that usually the girl students, especially in the rural area,s drop-out of schools at the primary stage itself. I would like to know the reasons for this; and also, whether the hon. Minister has taken any steps to reduce the drop-out rate among girls in the rural areas. I would also like to know whether there is any proposal to provide transport facilities, exclusively for girls, belonging to the rural areas, who could go to schools that are far away from their residences.

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: श्रीमन्, जहां तक ट्रांसपोर्ट का सवाल है, उसका तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि रूरल एरियाज में एक किलोमीटर के अंतर्गत स्कूल हैं और अधिक से अधिक दूरी डेढ़ किलोमीटर है। इसलिए इसके लिए ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करने का कोई औचित्य नहीं है। जहां तक लड़कियों के लिए शिक्षा का सवाल है, तो मुझे बताते हुए बहुत प्रसन्नता है कि अभी जो जनगणना हुई है, उससे यह पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की शिक्षा बहुत तेजी से बढ़ी है। सारे देश में वह 20-21 प्रतिशत बढ़ी है और पुरुषों की शिक्षा से कहीं अधिक बढ़ी है, विशेष कर ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अधिक बढ़ी है। इसके लिए दो बार हमें अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर नोमा पुरस्कार भी मिला है कि हमने महिला शिक्षा के क्षेत्र में बहुत प्रगति की है। इस बात के लिए हमारी पूरी कोशिश है कि महिलाओं की शिक्षा की दर बढ़ाई जाए और जेंडर गैप बहुत कम किया जाए।

श्री मोती लाल वोरा: माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कितने स्कूल्स भवन-विहीन हैं और कितने स्कूलों में शिक्षकों की संख्या एक है। दूसरे, आपने सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रत्येक जिले में जो प्लान बनाया है, उसकी रूपरेखा क्या है और तीसरे आपने इसमें "मिड डे मील" का भी उल्लेख किया है, तो मिड डे मील में बच्चों को कितना अनाज दिया जाता है। महोदय, मैंने सुना है कि वह अनाज बहुत ही घटिया किस्म का होता है और बच्चों ने उसे लेने से इंकार ही कर दिया है। तो क्या माननीय मंत्री जी के पास ऐसे स्कूलों से कोई शिकायत आई है जहां बच्चों को दोपहर का भोजन दिया जाता है?

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: सभापति जी, जहां तक सर्व-शिक्षा अभियान के संबंध में आपने बताया, उस के बारे में कई बार मैं सदन को अवगत करा चुका हूं कि हमारा लक्ष्य 2003 में सारे 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को स्कूल से सम्बद्ध करने का है। इसके लिए जहां कहीं से भी प्रोजेक्ट्स आए हैं, उन सारे प्रोजेक्ट्स को हमने स्वीकृत किया है, उनको धनराशि भी दे दी है।

हम ने डीपीईपी और सर्व-शिक्षा अभियान मे मिलाकर 5100 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की है। अब मूल प्रश्न में इस बात का संकेत नहीं था कि कहां भवन नहीं है, किस गांव में नहीं है - यह जानकारी प्राप्त करके आपको दी जा सकती है। इस समय वह जानकारी मैं नहीं दे सकता कि कितने भवन-विहीन स्कूल्स हैं। हां, कितने भवन हमने बनाए हैं, वह जरूर मैंने आपको जानकारी दे दी है। हम कंस्ट्रक्टिव काम करते हैं, कितने भवनविहीन हैं, आपको योगदान उस में रहा है और आप उस बारे में बेहतर जानते होंगे। हम तो भवन बना रहे हैं और उसकी जानकारी आपको दे दी है। जहां तक ''मिड डे मील'' का संबंध है, मैं, आपको अवगत कराना चाहता हूं कि इस समय 18 राज्यों में यह स्कीम लागू है जिसमें से 10 राज्यों में पूर्णत: पका-पकाया भोजन देने की व्यवस्था है, एक में आंशिक रूप से दिया जा रहा है और एक में अभी स्टार्ट किया है और बाकी में भी आंशिक रूप से दिया जा रहा है।

श्री सभापति: यह जवाब आपको प्रश्न 246 के उत्तर में देना पड़ेगा।

श्री मोती लाल वोरा: माननीय सभापति महोदय, माननीय विद्वान मंत्री जी से तो यह अपेक्षा की जाती है कि जब वे सदन में आएं इस बात की जानकारी लेकर आएं कि कितने भवन नहीं बने हैं, कितने स्कूल्स भवन-विहीन हैं।

डॉ॰ मुरली मनोहर जोशी: श्रीमन्, उनकी जानकारी इनके पास पहले से है क्योंकि ये भवन-विहीन छोड़कर आए थे।

श्री मोती लाल वोरा: माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक और प्रश्न पूछना चाहता हूं। मुझे जानकारी है कि जो स्कूल्स झाड़ के नीचे लगते है और कई स्कूलों में शिक्षक हैं ही नहीं, तो माननीय मंत्री महोदय आने वाले समय में इस बात की व्यवस्था करेंगे कि भवन-विहीन स्कूलों में भवन बन जाएं और जहां पर शिक्षक नहीं हैं, वहां शिक्षक हो जाएं। महोदय, आखिरी प्रश्न मैंने घटिया किस्म के ''मिड डे मील'' का पूछ था।

श्री सभापति: मिड डे मील का क्वैश्चन आगे आ रहा है। प्रश्न संख्या-243.

Increase in college fees

*243. DR. C. NARAYANA REDDY: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether there is any proposal to increase fees of college students of general and professional courses;

(b) if so, by when it is likely to be implemented; and